

सम्पादकीय...

अपनी सेहत को दाँव पर लगाने पर लोग आमादा

लोग खुद ही अपनी सेहत को दांव पर लगाने पर आमादा हों, तो उस समाज को आखिर कौन बचा सकता है? डॉक्टर चेतावनी देते-देते थक गए हैं कि प्रदूषण जानलेवा भी हो सकता है। मगर जागरूकता और जवाबदेही का अभाव जस-का-तस है।

छठ के सौके पर दिल्ली में यमना के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी

छठ के मासिक पर दल्ला में यथुना के प्रदूषण पर आम आदमी पाटा और भारतीय जनता पार्टी के बीच तू-तू-मैं मैं अब इतनी आम हो गई है कि लोग उससे ऊबने लगे हैं। मुद्दा है कि जब यह स्थायी समस्या है, तो छठ के बाद उस पर इन दोनों पार्टियों का ध्यान क्यों नहीं होता, जिनकी केंद्र और (केंद्र शासित) प्रदेश में सरकारें हैं? फिर सामान्य दिनों में नागरिक समाज को भी इसकी कोई फिक्र नहीं होती। यही हाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस सीजन में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण की है। फिर वही हुआ। एक और दिवाली आई और फिर दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर से ढक गया। पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ कागज पर रहा। लोगों ने जितनी मांग की, उतने पटाखे दुकानों में बिके, लोगों ने खरीदे और मन भर कर जलाए भी। अब लोग खुद ही अपनी सेहत को दांव पर लगाने पर आमादा हों, तो उस समाज को आखिर कौन बचा सकता है? डॉक्टर चेतावनी देते-देते थक गए हैं कि प्रदूषण सिर्फ थोड़ी-सी खांसी ही नहीं देता, बल्कि यह जानलेवा तक साबित हो सकता है। मगर भारत में जागरूकता और जवाबदेही का अभाव जस-का-तस है। अब इस क्रम में एक अंतरराष्ट्रीय पहलू भी जुड़ा है। पाकिस्तान भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव झेल रहा है। खासकर लाहौर शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह कम दिलचस्प नहीं कि प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर में खराब होती हवा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि भारत से आने वाली हवा अपने साथ प्रदूषण लेकर आती है, जिससे लाहौर की हवा खराब हो रही है। जबकि खुद पाकिस्तान में तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। इसके अलावा खेती की पद्धति, जैव ईंधन और कचरे को जलाना और धूल इसके अन्य पहलू हैं। मगर गंभीर समस्या पर अगंभीर और बे-ईमान रुख की संस्कृति पाकिस्तान में भी कोई कम नहीं है। बहरहाल, ऐसे नजरियों से कुछ हासिल नहीं होगा, यह बात हर जागरूक व्यक्ति अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

जलवायु संकट अभी भी मुद्दा नहीं

जलवायु संकट देश, नस्ल, धर्म और जाति के भेद के बिना सभी को मार रहा है, बरबादी की ओर ले जा रहा है लेकिन देशों और नेताओं के लिए अभी भी मुद्दा नहीं बना है। वर्ष 2024 रिकार्ड बना रहा है। रोजाना जबरदस्त गर्मी और विनाशकारी तूफान की खबरें आ रही हैं। लोगों की जिंदगी और जीविका के साधन ताश के पत्तों के ढेर की तरह ढहते दिख रहे हैं। इस साल गर्मी के मौसम में ऐसे मौके भी आएं जब सब कुछ नष्ट होना लगभग अवश्यभावी दिख रहा था। मौसमी उन्माद के साथ-साथ बीमारियों में भी बढ़ोतरी है। बीमारियां अजीब और अप्राकृतिक हैं।

हाल में हमारे पारिवारिक चिकित्सक ने बताया कि इस प्रकार का डेंगू फैल रहा है जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स की संख्या ही नहीं घटती बल्कि एक दिन बुखार आता है और उसके बाद कई दिनों तक नहीं आता और एसजीपीटी और एसजीओटी (लीवर की स्थिति बताने वाले दो हारमोन) के स्तर में तेज वृद्धि होती है। इसलिए यदि आपको आज बुखार है तो मेहरबानी करके कल ही अपनी जांच करवा लें। जोखिम उठाना ठीक नहीं। काफी जटिल स्थितियां का दौर है। और कोई भी इन जटिलताओं की मूल वजह दृ जलवायु में बदलाव दृ को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। न तो राजनैतिक बहस-मुबाहिसों में और न चुनावी चर्चाओं में इसका जिक्र होता है। पिछली गर्मियों में हुए हमारे आम चुनाव के दौरान जलवायु संकट चर्चा का मुद्दा नहीं था। इन दिनों दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी भी छाटे-बड़े राजनैतिक दल या उसके किसी नेता ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

सुष्मिता सेन इरादों को अमल में लाने में रखती हैं विश्वास

अभिनन्त्री सुष्ठिमा सेन, जिन्हें आखिरी बार स्ट्रीमिंग क्राइम-थ्रिलर सीरीज आर्या सीजन 3 में देखा गया था, इरादों

A close-up portrait of a woman with dark, wavy hair. She is smiling warmly at the camera. She is wearing a black and white horizontally striped top and a gold-toned necklace with a small pendant. The background is plain and light-colored. The entire image is enclosed within a decorative border featuring a repeating pattern of circles and dots.

कानूनी वायरे में कैसे लाए जाएं चुनावी वायदे

चुनाव घोषणा पत्रों और आज के दृष्टि और संकल्प पत्रों में किए गयदों और उन्हें लागू किए जाने को लेकर ठोस शोध जरूरी है। लेकिन मोटे तौर पर इनमें दर्ज ज्यादातर वायदे पूरे हो ही नहीं पाते। इसलिए मतदाताओं के एक वर्ग अलग ढंग से सोचने लगा है। चुनाव घोषणा पत्रों में किए गयदों को पूरा न कर पाने को लेकर सत्ता में आने वाला हर राजनीतिक दल मतदाताओं और विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता के चलते इन आलोचनाओं से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने अब चुनाव घोषणा पत्र जारी करना बंद कर दिया है। 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उत्तरी कांग्रेस ने राज्य के लिए विजन डाक्युमेंट जारी किया। इसके बाद सभी दलों ने चुनाव घोषणा पत्र के शीर्षक को तकरीबन त्याग दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले संकल्प पत्र जारी करती है तो कांग्रेस अब गारंटियां देने लगी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पांच गारंटी देने का वादा किया। जो उसके लिए बहुत हिट रहा। अब पार्टियां गारंटी देती हैं, दृष्टि पत्र प्रस्तुत करती हैं और संकल्प पत्र प्रस्तुत करती हैं। गारंटी और संकल्प जैसे शब्द एक तरह से गवाह हैं कि राजनीतिक दलों के वायदों को लेकर मतदाताओं का एक बड़ा अब आलोचनात्मक रूख ही नहीं रखता है, बल्कि उन पर भरोसा भी नहीं करता। घोषणा पत्र भले ही अब गारंटी या दृष्टि या संकल्प पत्र में तबदील हो गए हों, लेकिन अब भी उनकी साख नहीं ही है हित उम्मीद ऐसा निर्देश कदम भी अ अनुर्मा सुनवा पत्रों हालांकां को ले उठे। एक न कोर्ट सुनाय तमिल देश आयोग दलों संबंध दिया – चु उम्मीद करने प्रक्रिय घोषण जैसे उ जारी आन वे निष्पक्ष सकत सामान पहले ऐसी भी क नहीं लेकर

ही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य से लोक हित के तमाम कदम उठाने को लेकर उम्मीद तो करता है, लेकिन राज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं बनाता। नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य या सरकार कदम नहीं उठाती तो किसी को भी किसी भी अदालत में इसकी शिकायत की ना तो अनुमति है और ना ही कोई अदालत ऐसी सुनवाई कर भी सकती है। चुनाव घोषणा पत्रों की भी कुछ ऐसी ही रिथ्टि है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा पत्रों को लेकर अदालतों के सामने सवाल नहीं उठे। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को अपना फैसला सुनाया था। एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सलाह से चुनावी घोषणापत्र के संबंध में दिशा—निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था,— चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने और यह देखने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर आंच ना आए, घोषणापत्र को लेकर निर्देश जारी करे। जैसे आयोग आदर्श आचार संहिता के निर्देश जारी करता है। — आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसे आदेश दे सकता है। — अदालत को पता है कि सामान्यतया राजनीतिक दल मतदान के पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास किसी भी कार्य को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं होता है। फिर भी, घोषणा पत्र को लेकर अपवाद बनाया जा सकता है, क्योंकि

चुनावी घोषणापत्र का उद्देश्य सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श के बाद साल 2015 में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर गाइड-लाइन जारी की थी। इसके अनुसार, — चुनाव घोषणापत्र में संवैधानिक आदर्शों और सिद्धांतों से इतर कुछ भी नहीं होगा और यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा। — संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों को नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने के आदेश हैं, इसलिए चुनावी घोषणा पत्रों में ऐसे कल्याणकारी उपायों के वायदे पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि, राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए, जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर असर पड़ सकता है या मतदाताओं पर उनके मतादिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव पड़ने की आशंका हो। — पारदर्शिता, समान अवसर और वायदों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र में किए गए वादे स्पष्ट हों और इसे पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, इसकी भी जानकारी हो। मतदाताओं का भरोसा उन्हीं वादों पर हासिल करना चाहिए, जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो। दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग की गाइड लाइन भी बहुत प्रभावी नहीं



हो पा रही है। हवा-हवाई वायदे भी खूब किए जा रहे हैं। इनमें रोजगार और नौकरियों को लेकर की जाने वाले वायदे पहले नंबर पर हैं। कल्याणकारी योजनाएं भी इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं से संबंधि वायदे करते वक्त उन्हें पूरा करने के लिए जुटाई जाने वाली रकम और उनके स्रोत और तरीकों की जानकारी नहीं देते। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता का दबाव ही है कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वायदे खूब हो रहे और हर राजनीतिक दल अपने ढंग से लागू भी कर रहा है। भले ही राज्य के खजाने की हालत खस्ता ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि उस पर खर्च होने वाले फंड के स्रोत को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही। साफ है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन इस संदर्भ में नाकाम लग रही है। मौजूदा आर्थिकी में लाभ पर जोर है, रोजगार का सवाल लगातार पीछे छूटा जा रहा है। इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि राजनीतिक दल इसी आर्थिकी को आगे बढ़ाने के साथ ही रहा। चूंकि वोटरों के हाथ बंदों हुए हैं, इसलिए वे भी सवाल उठाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहां पर याद आता है, संविधानसभा के सदस्य अनंत शयनम अयंगार के वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चाबुक के तरक्क के विरोध में दिया था तब उन्होंने जनता की ताकत पर भरोसा जाता हुए कहा था कि पांच साल में एक बार जब चुनाव होंगे, तब मतदाताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे उन्हीं लोगों को न चुनें जो जनता की राय से अलग हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर हवाई वायदे ना हों और जो किए जाएं उन्हें लागू कैसे किया जाए? निश्चित तौर पर इसके लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी आगे आना होगा। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था इस आत्मनियन्त्रण करने से रही। चूंकि वायदों में ही सबका फायदा है।

साहित्य के नाम पर मनोरंजन का मंच

पिछले साल हिंदी के प्रख्यात लेखक एवम संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने इसलिए इस समारोह का बहिष्कार किया था कि उनसे आयोजकों ने पूछा था कि वे पहले सूचित करें कि वे मंच पर क्या बोलेंगे। लेकिन इस बार आइटम गर्ल को बुलाए जाने से विवाद अधिक है। जैसा हित्य के नाम पर मनोरंजन का मंच सजाने पर उस मंच की शोभा बढ़ाने की बजाय अगर लेखक जन आदोलनों में शामिल हों और लेखन, पठन का अपना मंच सजाएं तो क्या वह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? पिछले कुछ दिनों से हिंदी साहित्य की दुनिया में हंगामा बरपा हुआ है। एक टीवी चैनल के साहित्यिक कार्यक्रम में लेखकों के साथ-साथ बॉलीवुड के सितारों को बुलाए जाने के कारण सोशल मीडिया पर यह हंगामा मचा हुआ है। इस बीच पिछले दिनों दो लेखक संगठनों के दो पदाधिकारियों ने इस्टीफा भी दे दिया, जिससे इस मामले ने अधिक तूल पकड़ लिया। एक लेखक के बारे में कहा जा रहा है कि उसने टीवी चैनल के साहित्योत्सव में जाने पर अपने मित्र लेखक द्वारा तंज किए जाने के कारण इस्टीफा दिया है। जो लोग इस तरह के समारोहों में जा रहे हैं उनका तर्क है कि लेखकों को हर मंच पर जाना चाहिए और इस तरह जनता से जुड़ना चाहिए क्योंकि हमारे लेखक संगठन जनता से नहीं जुड़े हैं। इन लेखकों का कहना है कि हम किसी भी मंच पर जाएं लेकिन हमें अपनी बात खरी-खरी कहनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस टीवी चैनल के साहित्योत्सव के विरोधी हैं उनका तर्क है कि अगर बॉलीवुड के लोगों को बुलाना है तो साहित्य की आड़ में यह क्यों किया जा रहा, इसे इसाहित्य आज तक्य की बजाय शमनोरंजन आज तक्य के नाम से किया जाए। आखिर साहित्य के जलसे में आइटम गर्ल को क्यों बुलाया जा रहा? उनका तर्क यह भी है कि इस तरह के टीवी चैनलों के मंच सांप्रदायिक लोगों द्वारा संचालित हैं और वह साहित्य को बाजार बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए उनके मंच से उनके खिलाफ बात नहीं कहीं जा सकती और अगर किसी ने कहा भी तो उसका व्यापक असर नहीं होने वाला है क्योंकि ज्यादातर वक्ता बाजार के समर्थक ही हैं। पिछले साल हिंदी के प्रख्यात लेखक एवम संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने इसलिए इस समारोह का बहिष्कार किया था कि उनसे आयोजकों ने पूछा था कि वे पहले सूचित करें कि वे मंच पर क्या बोलेंगे। लेकिन इस बार आइटम गर्ल को बुलाए जाने से विवाद अधिक है। अब हिंदी के लेखकों में धूर्वीकरण भी हो गया है। लेखिकाओं में भी विभाजन हो गया है। एक वर्ग आइटम गर्ल को बुलाए जाने का समर्थक है तो एक वर्ग विरोधी। इस तरह साहित्य की दुनिया में इन दिनों उथल-पुथल अधिक है। हिंदी के लेखकों का एक धड़ा, जिनमें कुछ प्रगतिशील और कलावादी भी हैं, वह इस समारोह में भाग ले रहा है, जबकि एक धड़ा उसका लगातार विरोध कर रहा है। भाग लेने वालों में पुरुषोत्तम अग्रवाल, अरुण कमल और गौहर राजा जैसे लोग हैं तथा बाबुषा कोहली, अनुराधा सिंह और लवली गोस्वामी एवम जोशाना बनर्जी जैसी कवयित्रियां भी। कुछ साल पहले इसी टीवी चैनल के साहित्यिक कार्यक्रम में हिंदी के प्रगतिशील जनवादी कवि राजेश जोशी के भाग लेने पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जनवादी लेखक इस समारोह में जाते रहे। अब प्रगतिशील लेखक संगठन ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक प्रस्ताव पारित कर कॉरपोरेट के समारोहों में भाग लेने से लेखकों को मना किया है। पर दो अन्य वाम लेखक संगठनों ने इस तरह का प्रस्ताव नहीं पारित किया है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह के आयोजन को लेकर हिंदी में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है? पिछले 10-15 वर्षों से हिंदी में लिट. फेस्ट की संख्या काफी बढ़ी है और उनमें हिंदी के लेखक बुलाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को लिट. फेस्ट में नहीं बुलाया जा रहा है वह अपनी कुंठा के कारण उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिंदी जगत में कुछ ऐसे लेखक हैं, जो ऐसे मंचों पर कभी जाते ही नहीं। वह इन मंचों को तमाशाई, अगम्भीर, उत्सव धर्मी अधिक मानते हैं। इन मंचों से कायदे की कोई बात नहीं कहीं जा सकती है और न सुनी जा सकती है। लेकिन लेखकों का एक तबका यह कहता है कि हमें बाजार से परहेज नहीं करना चाहिए। आखिर हमारी किताबों को बाजार तलाशेंगे तो अधिक पाठकों तक पहुंचेंगे। शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर आज का लेखक अपनी किताब का खुद प्रचार-प्रसार करता हुआ दिख रहा है। हिंदी में ऐसे भी लेखक हैं जो यह काम नहीं करते हैं और यह मानते हैं कि किताब का प्रचार-प्रसार करना प्रकाशक की जिम्मेदारी है ना कि लेखक की। इससे पहले हिंदी के लेखक अपनी किताबों का इस तरह प्रमोशन नहीं करते थे और प्रचार नहीं करते थे। यह सारी जिम्मेदारी पहले प्रकाशक की थी। ऐसे में लेखक प्रकाशक का यह काम क्यों कर रहे हैं?

फिल्मी दुनिया/सेहत

**महिला के संघर्ष को बरवूबी बताएं करती हैं अवार्ड विनिंग
व्हलासिक फिल्म ढाई आखर, 22 नवम्बर को होगी रिलीज**

निर्देशक प्रवीन अरोड़ा की फिल्म ढाई आखरय एक कलासिक लव स्टोरी है, जो एक महिला की अपनी पहचान ढूँढने की कोशिश में किए गए संघर्ष को बख्बौदी बयान करती है। ये फिल्म 22 नवम्बर को पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। हिन्दी के वरिष्ठ लेखक अमरीक सिंह टीवी के उपन्यास टीर्थटन के बाद प्रथम आधारित फिल्म ढाई आखर इर्षता नाम की



पीरियड्स के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग प्रेग्नेंसी के लक्षण तो नहीं ? जानें क्या हैं पूरा सच

मिठाई और कार्बोहाइड्रेट की लालसा मासिक धर्म के दौरान आम है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल चरण के दौरान, एस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर मिठाई और कार्बोहाइड्रेट की लालसा पैदा कर सकते हैं। आपके पीरियड्स के दौरान मिठाई और कार्बोहाइड्रेट की लालसा पीएमएस का एक सामान्य हिस्सा है और यह जैविक और मनोवैज्ञानिक फारकों के संयोजन के कारण होता है। आपके मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान, एस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर मिठाई और कार्बोहाइड्रेट की लालसा को बढ़ा सकते हैं। जब आप मिठाई और एस्ट्रार्चयुक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपका शरीर सेरोटोनिन छोड़ता है, जो आपके मूड को बढ़ा सकता है। मिठाई वाले से शामालों पीएमएस के साथ आने वाली भावनाओं से चिपाने में मदद मिल सकती है।



